

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन

दि ग्राम टुडे, कानपुर। (भरत पांडे,

रितेश शर्मा)

आपको बता दें कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शर्करा उद्योग में जल और अपशिष्ट प्रबंधन - उभरती चुनौतियां, विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन संस्थान में किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अपर निदेशक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली रीना सातवन ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि 200 लीटर / टन गन्ने हेतु निर्धारित की गई सीमा से आगे बढ़कर इफ्लूएंट डिस्चार्ज की मात्रा को



कम करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों और मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाया जाए, ताकि इसका उपयोग सिंचाई के पानी के रूप में या अन्यत्र किया जा सके। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने अपने

संबोधन में सुझाव दिया कि इफ्लूएंट डिस्चार्ज की मात्रा पर जोर देने की अपेक्षा ताजे पानी की खपत और इफ्लूएंट डिस्चार्ज की गुणवत्ता पर बल देते हुए मानदंडों को और अधिक कठोर बनाया जा सकता है।

आधुनिक तकनीकी को इस्तेमाल कर इफ्लूएंट डिस्चार्ज को कम करें चीनी मिलें

❑ शर्करा उद्योग में जल और अपशिष्ट (इफ्लूएंट) प्रबंधन- उभरती चुनौतियां विषय पर हुई संगोष्ठी

कानपुर, 10 मई। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित शर्करा उद्योग में जल और अपशिष्ट (इफ्लूएंट) प्रबंधन- उभरती चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, नई दिल्ली के अपर निदेशक सुश्री रीना सातवन ने जोर देते हुए कहा कि 200 लीटर प्रति टन गन्ने के लिए निर्धारित की गई सीमा से आगे बढ़कर इफ्लूएंट डिस्चार्ज की मात्रा को कम करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाया जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक डा. देवेन्द्र सोनी ने पवित्र गंगा नदी के बेसिन में स्थित शर्करा कारखानों द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा करते हुए शर्करा उद्योग में और सुधार के लिए अन्य उद्योगों में प्रचालित जल उपचार की अन्य



कार्यक्रम में शामिल मुख्यअतिथि।

आधुनिक तकनीकी को अपनाने का सुझाव दिया। एनएसआई के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने सुझाव देते हुए बताया कि इफ्लूएंट डिस्चार्ज की मात्रा पर जोर देने की अपेक्षा, ताजे पानी की खपत और इफ्लूएंट डिस्चार्ज की गुणवत्ता पर बल देते हुए मानदंडों को और अधिक कठोर बनाया जा सकता है। गन्ना आधारित शर्करा उद्योग किसी

भी अन्य उद्योग है। जहां क्रज्जे माल यानी गन्ने में ही 70-72 प्रतिशत पानी होता है। जो प्रोसेसिंग के दौरान बाहर निकलने के लिए बाध्य होता है। और इसलिए खुद की प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी अतिरिक्त पानी का डिस्चार्ज होना निश्चित है। जिसका उपयोग सिंचाई सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता

है। इस पानी की माला प्रक्रिया के स्वरूप, वातावरण की परिस्थितियों, गन्ने की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न हो सकती है। शर्करा अभियांत्रिकी के अस्सिस्टेंट प्रो. अनूप कुमार कनौजिया ने गंगा बेसिन में स्थित शर्करा कारखानों और डिस्टिलरीज में पानी और इफ्लूएंट मैनेजमेंट का एक अवलोकन किया। सरस्वती शुगर मिल्स, लि. मेसर्स राजीव मिश्रा ने एक अभिनव माडल का वितरण प्रस्तुत किया जिसमें शर्करा कारखानों और डिस्टिलरीज वाले शर्करा परिसर को ताजे पानी के उपयोग के बिना और बिना किसी इफ्लूएंट डिस्चार्ज के संचालित किया जा रहा है। बलरामपुर शुगर मिल्स लि., मेसर्स डीसीए श्रीराम लिमिटेड और मेसर्स डालमिया भारत शुगर लिमिटेड द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं। जिसमें ताजे पानी की खपत को लगभग शून्य के लिए उनके द्वारा किये गये प्रयासों पर प्रकाश डाला।

एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में सम्पन्न



कानपुर (नगर प्रचार समिति)। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शर्करा उद्योग में जल और अपशिष्ट (इफ्लुएंट) प्रबंधन-उपराती चुनौतियाँ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, आज राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में सम्पन्न हुई। इसमें हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

सूत्री रीति सातका, अपर निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि 200 लीटर/टन गले हेतु निर्धारित की गई सीमा में अग्रे बढ़कर इफ्लुएंट डिस्चार्ज की मात्रा को कम करने के लिए सर्वोत्तम तकनीकों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाया जाए ताकि इसका उपयोग सिंचाई के पानी के रूप में या अन्यत्र किया जा सके। उन्होंने कहा कि शर्करा उद्योग को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की मदद से तैयार किए गए चार्टर का फायदा करते हुए प्रोसेसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ताजे पानी की खपत को कम करने की आवश्यकता है। डॉ. देवेन्द्र सोनी, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ने पवित्र रंग नदी के बेसिन में स्थित शर्करा कारखानों द्वारा किया गए प्रयासों की प्रशंसा करते हुए शर्करा उद्योग में और सुधार के लिए अन्य उद्योगों में प्रचलित जल उपचार की अन्य आधुनिक तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया। श्री नरेंद्र मोहन, निदेशक, राष्ट्रीय

शर्करा संस्थान ने अपने संबोधन में सुझाव दिया कि इफ्लुएंट डिस्चार्ज की मात्रा पर जोर देने की अपेक्षा, ताजे पानी की खपत और इफ्लुएंट डिस्चार्ज की गुणवत्ता पर बातें होनी चाहिए और अधिक कठोर कानून लागू किए जाएं। गुणवत्ता पर जोर देने का मतलब है कि प्रोसेसिंग के दौरान बाहर निकलने के लिए क्षमता होनी चाहिए और इसलिए खुद की प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी अतिरिक्त पानी का डिस्चार्ज होना निश्चित है, जिसका उपयोग सिंचाई सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस पानी की मात्रा प्रक्रिया के स्वरूप, बनावट और परिस्थितियों, गले की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न हो सकती है।

शर्करा अभियांत्रिकी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अनूप कुमार कर्नीशाह ने गंगा बेसिन में स्थित शर्करा कारखानों और डिस्टिलरीज में पानी और इफ्लुएंट मैनेजमेंट का एक अद्वितीय प्रस्तुत किया। संस्थान और उद्योग के संयुक्त प्रयासों से पिछले तीन वर्षों के दौरान जहां शर्करा कारखानों में ताजे पानी की खपत में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई है, वहीं औसत इफ्लुएंट डिस्चार्ज भी 180 से घटकर 150 लीटर प्रति टन गले तक हो गया है जो कि लगभग 20% कम है। हालांकि पर आधारित डिस्टिलरीज में भी ताजे पानी की खपत में औसतन 48 प्रतिशत की कमी आई है और जबकि नए यूनिट्स लिफ्ट डिस्टिलरीज पर काम करते पानी पानी

हैं। श्री राजीव मिश्रा, मेसर्स सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड, यमुनानगर, हरियाणा ने एक अभिनव सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें शर्करा कारखाने और डिस्टिलरीज वाले शर्करा परिसर को ताजे पानी के उपयोग के बिना और बिना किसी इफ्लुएंट डिस्चार्ज के संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए अनुकरणीय हो सकता है। यद्यपि इसके लिए कुछ अतिरिक्त पूंजी और परिचालन लागत की आवश्यकता होगी, परन्तु पानी की कमी के विषय को देखते हुए इसका फायदा करने की आवश्यकता है। मेसर्स कलदासपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, मेसर्स डीसीएम भारत शुगर लिमिटेड और मेसर्स डालमिया भारत शुगर लिमिटेड द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें ताजे पानी की खपत को लगभग शून्य करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। तथ्यांश निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि विभिन्न कारणों से इफ्लुएंट डिस्चार्ज की मात्रा के साथ कुछ समस्याएं हैं और शर्करा कारखानों के बदले हुए कामकाजी मॉडल के कारण भी बिना किसी उपचार और इथेनॉल उत्पादन के प्राथमिकता दी जा रही है। अतएव इस विषय को उस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की बात उन्होंने रखी। मेसर्स युवाई ट्रांसमिक्सी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स पैक्स एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-बीओमिक्स प्रदाताओं द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं।

‘तकनीकी मदद से कम करें शुगर मिलों का अपशिष्ट’

कानपुर (एसएससी)। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त आयोजी में शर्करा उद्योगों से निकलने वाले जल और अपशिष्ट (इफ्लुएंट) को कम करने के लिये तकनीकी सहायता देने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों में प्रचलित जल उपचार के तरीकों को अपनाने का सुझाव दिया गया।

शर्करा उद्योग में जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित की गई संगोष्ठी



असिस्टेंट प्रबंधन-उपराती चुनौतियाँ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की अपर निदेशक रीति सातका ने कहा कि 200 लीटर प्रति टन गले के लिये निर्धारित सीमा में अग्रे बढ़ कर इफ्लुएंट डिस्चार्ज की मात्रा को कम करने के लिये सर्वोत्तम तकनीकों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाया जाए ताकि इसका

उपयोग सिंचाई के पानी के रूप में किया जा सके। उन्होंने कहा कि शर्करा उद्योग को शर्करा शर्करा संस्थान की मदद से तैयार किये गये चार्टर का फायदा करते हुए प्रोसेसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ताजे पानी की खपत को कम करने की

जरूरत है। वहीं बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक देवेन्द्र सोनी ने शर्करा उद्योग में और सुधार के लिये अन्य उद्योगों में प्रचलित जल उपचार की अन्य आधुनिक तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया। वहीं संस्थान के निदेशक श्री नरेंद्र मोहन ने सुझाव दिया कि इफ्लुएंट

डिस्चार्ज की मात्रा पर जोर देने की अपेक्षा, ताजे पानी की खपत और इफ्लुएंट डिस्चार्ज की गुणवत्ता पर बातें होनी चाहिए और अधिक कठोर कानून लागू किए जाएं। गुणवत्ता पर जोर देने का मतलब है कि प्रोसेसिंग के दौरान बाहर निकलने के लिए क्षमता होनी चाहिए और इसलिए खुद की प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी अतिरिक्त पानी का डिस्चार्ज होना निश्चित है, जिसका उपयोग सिंचाई सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। शर्करा अभियांत्रिकी के असिस्टेंट प्रोफेसर अनूप कुमार कर्नीशाह ने गंगा बेसिन में स्थित शर्करा कारखानों और डिस्टिलरीज में पानी व इफ्लुएंट मैनेजमेंट का एक अद्वितीय प्रस्तुत किया। संस्थान और उद्योग के संयुक्त प्रयासों से पिछले तीन वर्षों के दौरान जहां शर्करा कारखानों में ताजे पानी की खपत में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई है, वहीं औसत इफ्लुएंट डिस्चार्ज भी 180 से घटकर 150 लीटर प्रति टन गले तक हो गया है जो कि लगभग 20% कम है। हालांकि पर आधारित डिस्टिलरीज में भी ताजे पानी की खपत में औसतन 48 प्रतिशत की कमी आई है और जबकि नए यूनिट्स लिफ्ट डिस्टिलरीज पर काम करते पानी पानी

हैं। श्री राजीव मिश्रा, मेसर्स सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड, यमुनानगर, हरियाणा ने एक अभिनव सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें शर्करा कारखाने और डिस्टिलरीज वाले शर्करा परिसर को ताजे पानी के उपयोग के बिना और बिना किसी इफ्लुएंट डिस्चार्ज के संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए अनुकरणीय हो सकता है। यद्यपि इसके लिए कुछ अतिरिक्त पूंजी और परिचालन लागत की आवश्यकता होगी, परन्तु पानी की कमी के विषय को देखते हुए इसका फायदा करने की आवश्यकता है। मेसर्स कलदासपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, मेसर्स डीसीएम भारत शुगर लिमिटेड और मेसर्स डालमिया भारत शुगर लिमिटेड द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें ताजे पानी की खपत को लगभग शून्य करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। तथ्यांश निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि विभिन्न कारणों से इफ्लुएंट डिस्चार्ज की मात्रा के साथ कुछ समस्याएं हैं और शर्करा कारखानों के बदले हुए कामकाजी मॉडल के कारण भी बिना किसी उपचार और इथेनॉल उत्पादन के प्राथमिकता दी जा रही है। अतएव इस विषय को उस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की बात उन्होंने रखी। मेसर्स युवाई ट्रांसमिक्सी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स पैक्स एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-बीओमिक्स प्रदाताओं द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं।

एफ्लूएंट टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया जाए: रीना सातवन

→ एनएसआई और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुई गोष्ठी
→ विभिन्न राज्यों से आए अधिकारियों ने टेक्नोलॉजी विधि पर रखे अपने अपने विचार

नगरराज दर्पण समाचार

कानपुर । एफ्लूएंट विधि को और बेहतर तकनीक से किया जाए तो इसमें निकलने वाला पानी खेती में सिंचाई के काम आ सकता है । अभी भारी मात्रा में पानी व्यस्त हो रहा है अगर बेहतर टेक्नोलॉजी से इस पर शोध किया जाए तो वेस्टेज पानी खेती के उपयोग में लिया जा सकेगा । यह बात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं दिल्ली से आई अपर निदेशक रीना सातवन ने कही । एनएसआई और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त एक दिवसीय गोष्ठी में ना सिर्फ गुपार कंपनियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया बल्कि उत्तर प्रदेश



मध्य प्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक इनरखंड जैसे प्रदेशों से आए अधिकारियों ने भी इस विषय पर अपने अपने विचार रखे । सुश्री सातवन ने कहा कि यंत्रों की पिराई में जो वेस्टेज वाटर निकल रहा है उसे प्युरिफाई करने की आवश्यकता है । क्योंकि वेस्टेज पानी से जल प्रदूषण फैलता है इसलिए हमें चाहिए कि वेस्टेज पानी को भी

प्युरिफाई करके उसे सिंचाई के योग्य बनाया जाए । एनएसआई के निदेशक नरेंद्र मोहन ने कहा कि वर्तमान समय में एथेनॉल उत्पादन की प्राथमिकता दी जा रही है और सभी लोग इस टॉपिक पर लगातार शोध कर रहे हैं कि कम लागत में एथेनॉल को तैयार किया जाए । उन्होंने कहा कि उनके इंस्टीट्यूट में लगातार कई विषयों पर शोध किए जा

चुके हैं और आगे भी किए जा रहे हैं जिसके परिणाम प्रदेश के साथ-साथ भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं । चावनुद इसके नई टेक्नोलॉजी से शोध को और बेहतर तरीके से किया जा रहा है । गोष्ठी में मुख्य रूप से राजीव मिश्रा महेंद्र कुमार पादव समेत कई अधिकारियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए ।

Seminar on effluent mgmt held at NSI

TIMES NEWS NETWORK

Kanpur: One day national seminar on 'Water & Effluent Management in Sugar Industry: Emerging Challenges' jointly organized by National Sugar Institute and Central Pollution Control Board was held at NSI, Kanpur. It was attended by delegates from Haryana, Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka.

Additional Director, Central Pollution Control Board, New Delhi, Reena Satawan in her address stressed upon adoption of best available technologies and standard operating procedures for reducing the quantity of discharges further from the prescribed limit of 200 liters/ton of cane with quality suitable for use as irrigation water or even better.

The sugar industry is required to reduce fresh water consumption also to meet processing requirements by following the charter prepared with the help of National Sugar Institute, she said.

Regional Director, Central Pollution Control Board, Lucknow, Dr. Devendra Soni while praising the efforts made by the sugar factories situated in the holy river Ganga basin, suggested adoption of technology of water treatment from other industries

for implementation in sugar industry for further improvement.

Director, National Sugar Institute, Narendra Mohan, in his address suggested that instead of insisting on quantity of effluent discharge, the norms should stress on fresh water intake and quality of discharge, which may be made more stringent.

Sugarcane based sugar industry is different from any other industry, where raw material that is sugarcane itself contains 70-72% water which is bound to come out during processing and hence even after meeting own processing requirements, which vary to a larger extent, surplus water is likely to be discharged which can be used for various purposes including irrigation, he said.

Assistant Professor of Sugar Engineering, Anoop Kumar Kanaujia presented an overview of the water and effluent management in sugar factories and distilleries situated in Ganga basin.

Presentations were also made by M/s Balrampur Chini Mills Limited, M/s DCM Shriram Limited and M/s Dalmia Bharat Sugar Limited highlighting efforts made by them in reducing the fresh water consumption to almost zero.

Seminar on effluent management in sugar industry

PIONEER NEWS SERVICE ■ KANPUR

Reena Satawan, Additional Director, Central Pollution Control Board, New Delhi while addressing a one-day national seminar on "Water and Effluent Management in Sugar Industry-Emerging Challenges" on Wednesday jointly organised by National Sugar Institute (NSI) and Central Pollution Control Board (CPCB) stressed on adoption of best available technologies and standard operating procedures for reducing quantity of discharges further from the prescribed limit of 200 liters per tonne of cane with quality suitable for use as irrigation water or even better. She said sugar industry was required to reduce fresh water consumption also to meet processing requirements by following the charter prepared with the help of NSI. Dr Devendra Soni, Regional Director, CPCB, Lucknow, while praising the efforts made by sugar factories situated in the holy Ganga basin suggested adoption of water treatment technology from other industries for implementation in sugar industry for further improvement. Prof Narendra Mohan, Director, NSI, suggested that instead of insisting on quantity of effluent discharge, norms should stress on fresh water intake and quality of discharge which may be made more stringent. He said sugarcane based sugar industry was



different from any other industry where raw material like sugarcane itself contained 70-72 per cent water which was bound to come out during processing and hence even after meeting own processing requirements, which varied to a larger extent surplus water was likely to be discharged which can be used for various purposes, including irrigation. Anoop Kumar Kanaujia, Assistant Professor of Sugar Engineering presented an overview of the water and effluent management in sugar factories and distilleries situated in Ganga Basin. He said due to combined efforts of institute and industry, during the last three years while the fresh water consumption in sugar factories had come down by about 40 per cent, the average effluent discharge had also come down from 180 to 150 litre per tonne of cane that was by around 20 per cent or so. In the molasses based distilleries also there was average reduction in fresh water

consumption by 48 per cent and mostly they were found to be working on zero liquid discharge. Rajeev Mishra, Saraswati Sugar Mills Ltd, Yamunanagar, Haryana, presented details of an innovative model wherein their sugar complex comprising sugar factory and distillery was being operated without any use of fresh water and also with no effluent discharge. He said this may be a model for all to follow. He added that although it would require some additional capital and operational cost but looking to the issue of water scarcity this was needed to be followed. Presentations were also made by Balrampur Chini Mills Ltd, DCM Shriram Ltd and Dalmia Bharat Sugar Ltd highlighting efforts made by them in reducing the fresh water consumption to almost zero. However, there were issues with the quantity of discharges due to various reasons as highlighted by Prof Mohan and also due to changed working model of the sugar factories where power generation and ethanol production was being preferred. He said thus the issue was to be seen in that perspective. Trienviro Systems Pvt Ltd. and Paques Environmental Technology India Pvt Ltd also took part. Mahendra Yadav, coordinator, proposed the vote of thanks. A large number of delegates from Haryana, Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka took part in the seminar.

शुगर इंडस्ट्री का नया चार्टर तैयार करेगा एनएसआई

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। शुगर इंडस्ट्री का नया चार्टर अब राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) तैयार करेगा। संस्थान के निदेशक की अगुवाई में वैज्ञानिकों की टीम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुरूप चार्टर बनाएंगे। इसमें अत्याधुनिक तकनीक को भी शामिल किया जाएगा। यह फैसला राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुआ। इसमें देशभर के वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शुगर इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों ने जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर मंथन किया। संगोष्ठी में आए सुझाव व समस्या को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

■ अत्याधुनिक तकनीक को भी शामिल करेंगे

■ समस्या को लेकर रिपोर्ट तैयार की हो रही

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में सीपीसीबी की मदद से बुधवार को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसका विषय शर्करा उद्योग में जल और अपशिष्ट प्रबंधन-उभरती चुनौतियां रहा। संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने कहा कि शर्करा उद्योग में प्रयोग के लिए गन्ने में ही 70 से 72 फीसदी पानी होता है इसलिए प्रोसेसिंग के दौरान इसी पानी का इस्तेमाल किया जाए।

गंगा बेसिन की चीनी मिलों में ताजे पानी की खपत घटी

कानपुर। गंगा बेसिन में चल रही चीनी मिलों में ताजे पानी की खपत 40 फीसदी कम हुई है और इनसे निकलने वाला पानी भी 20 फीसदी कम हुआ है। प्रति टन गन्ने से निकलने वाला इंप्लूमेंट डिस्चार्ज 180 से घटकर 150 लीटर हो गया है। गन्ने के शीरे पर आधारित डिस्टिलरीज में भी ताजे पानी की खपत 48 फीसदी तक कम हुई है। ज्यादातर डिस्टिलरीज शून्य लिक्विड डिस्चार्ज पर काम कर रही हैं।

यह ब्योरा बुधवार को नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) में आयोजित शर्करा उद्योग में जल और अपशिष्ट प्रबंधन-उभरी चुनौतियाँ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में दिया गया। सेमिनार का आयोजन एनएसआई और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैनर तले किया गया। बोर्ड की अपर निदेशक रीना सातवन ने कहा कि चीनी मिलों से निकलने वाले पानी की उपलब्ध तकनीकों से सिंचाई के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. देबेंद्र सोनी ने गंगा बेसिन के शर्करा उद्योग में सुधार की तारीफ की। एनएसआई निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि गन्ने में 70 से 72 फीसदी पानी होता है जो प्रोसेसिंग के दौरान निकलता है। (व्युटी)